

Waive select taxes for companies in insolvency proceedings: Assocham

NEW DELHI: Industry body Assocham on Wednesday sought from the government slew of tax relief for companies against whom insolvency proceedings have been initiated.

"Where any outstanding liability, inclusive of any accrued interest is waived in accordance with the approved Resolution Plan, such waiver/write-back should not be subject to tax under both normal and Minimum Alternate Tax (MAT) provisions of the Income-tax Act, 1961," Assocham said in a letter to Central Board of Direct Taxes (CBDT). The chamber has also sought exemption from Section 50CA of the I-T Act for the companies which are being

revived under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

This section provides that the computation of capital gains would be done on the basis of fair value of the shares of the company even if these are transferred under the IBC package below the fair value.

Since MAT was not payable by a sick company on its book profits from the year in which it became sick, it is recommended that similar reliefs should be extended to the corporate debtor after the approved Resolution Plan is effected.

In the letter marked to the Financial Services Department as well as MCA, Assocham also sought that companies against

whom insolvency proceedings have been approved by the NCLT, they should be exempt from the General Anti Avoidance Rules (GAAR) provisions.

The resolution plans approved after factoring in these reliefs/concessions will result in quick revival of assets, freeing up liquidity for banks for further lending, increased economic activity, job creation, increased contribution to the exchequer and will have multiplier effect on the associated economy, Assocham said. Currently, non-performing loan resolution process is going on for 12 companies and this represent 25 per cent of total bad loans in the system NPLs. PFI



PHL Union MoS Civil Aviation Jayant Sinha conferred Pawan Hans award for Promoting Heli-Tourism & Remote Area Air Connectivity at a function organized by ASSOCHAM held in Delhi.

दिवाला प्रक्रिया में कंपनियों को कुछ करों से राहत मिले : एसोचैम

नई दिल्ली, (भाषा)। उद्योग संगठन एसोचैम सरकार से उन कंपनियों को कुछ करों से राहत देने की मांग की है जिनके खिलाफ दिवाला एवं शोधन अक्षमता की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को लिखे एक पत्र में एसोचैम ने कहा, किसी कंपनी की मंजूर की गई दिवाला की समाधान योजना के अनुसार अर्जित ब्याज समेत किसी बकाया देनदारी के लिए दी गई छूट पर आयकर अधिनियम-1961 के सामान्य और न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैटा प्रावधानों) के तहत कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उद्योग मंडल ने इसके अलावा कंपनियों को आयकर कानून की धारा 50 सीए से भी छूट देने को कहा है जिन्हें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत फिर से प्रभावी बना दिया गया है। इस धारा के तहत किसी कंपनी के पूंजीगत लाभ की गणना

उसके शेयरों के उचित मूल्य के आधार पर करने की सुविधा मिलती है भले ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया पैकेज के तहत उन्हें उचित मूल्य से नीचे पर हस्तांतरित कर दिया गया हो। एसोचैम का कहना है कि जिस प्रकार कोई बीमार कंपनी अपने घाटे में आने के साल में बहीखातों में अर्जित लाभ पर मैट का भुगतान नहीं करती है उसी प्रकार की राहत उन ठूण लेने वाली कारपोरेट कंपनियों को मिलनी चाहिए जो आईबीसी की समाधान योजना मंजूर कर चुकी है और प्रभाव में आ चुकी है। वित्तीय सेवा विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को लिखे गए पत्र में एसोचैम ने मांग की है कि जिन कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण से मंजूरी मिल चुकी है उन्हें सामान्य कर परिवर्जन रोधी अधिनियम (गारा) के प्रावधानों से भी छूट मिलनी चाहिए।